Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

अध्याय - 3

नियोजित विकास की राजनीति

भाग - 4

Satyaveer Yadav

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

औद्योगीकरण की तेज रफ्तार

दूसरी पंचवर्षीय योजना

- भारी उद्योगों के विकास पर जोर
- पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार
- पहली योजना का मूलयंत्र था → धीरज
- वहीं दूसरी योजना की कोशिश → तेज गति से संरचनात्मक बदलाव
  - हर दिशा में बदलाव की बात तय

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

प्रयास :-

- देशी उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात पर भारी शुल्क
- बिजली, रेल्वे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे।
- औद्योगीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नए आयाम दिए।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

II, शांति
राजीव गांधी

समस्याएँ :

- भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी।
- उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आंशका सताने लगी।
- योजनाओं को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

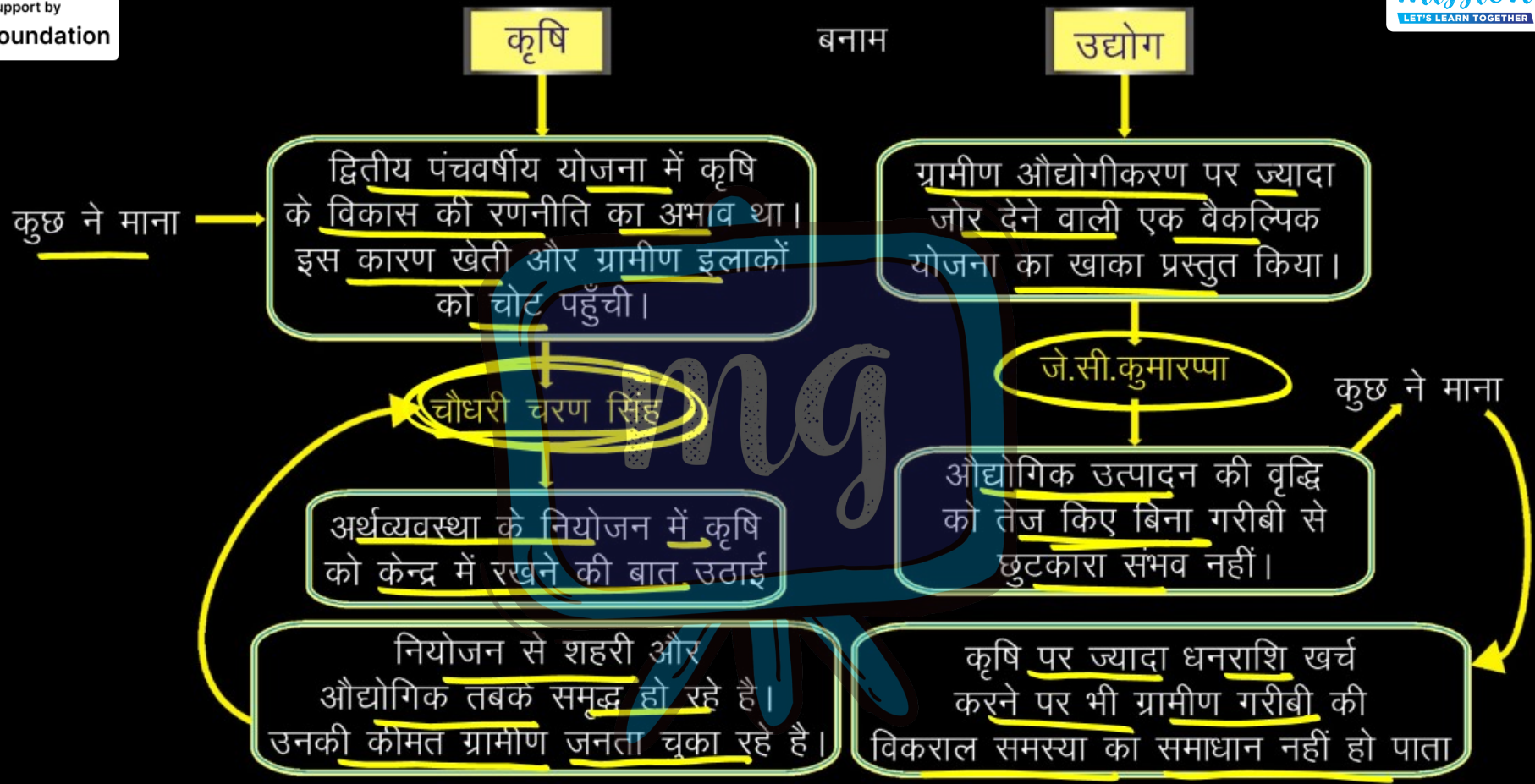
कृषि बनाम उद्योग



बड़ा सवाल – भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र

विकास के दो जाने–माने मॉडल

पूँजीवादी मॉडल

विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे

समाजवादी मॉडल

- निजी संपत्ति समाप्त
- हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण

दो मॉडल के मिले–जुले रूप को भारत ने अपनाया

मिश्रित अर्थव्यवस्था

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



- खेती - किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा।
- राज्य ने भारी उद्योगों को रखा।
- राज्य ने व्यापार नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किये।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आलोचनाएँ :-

- योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी।
- सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस/परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाये हैं।
- सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा आयद की है जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीजों के उत्पादन का बाजार प्रतिस्पर्धाविहीन है।
- सरकार ने नियंत्रण में जरूरत से ज्यादा चीजें रखीं हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

अन्य आलोचनाएँ :-

- सरकार ने जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा मद में कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की।
- सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने को तैयार नहीं थे - निजी क्षेत्र को मुनाफा
- सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यमवर्ग उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है।
- गरीबी का प्रतिशत कुछ जनसंख्या के अनुपात में भले ही कम हुआ हो लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

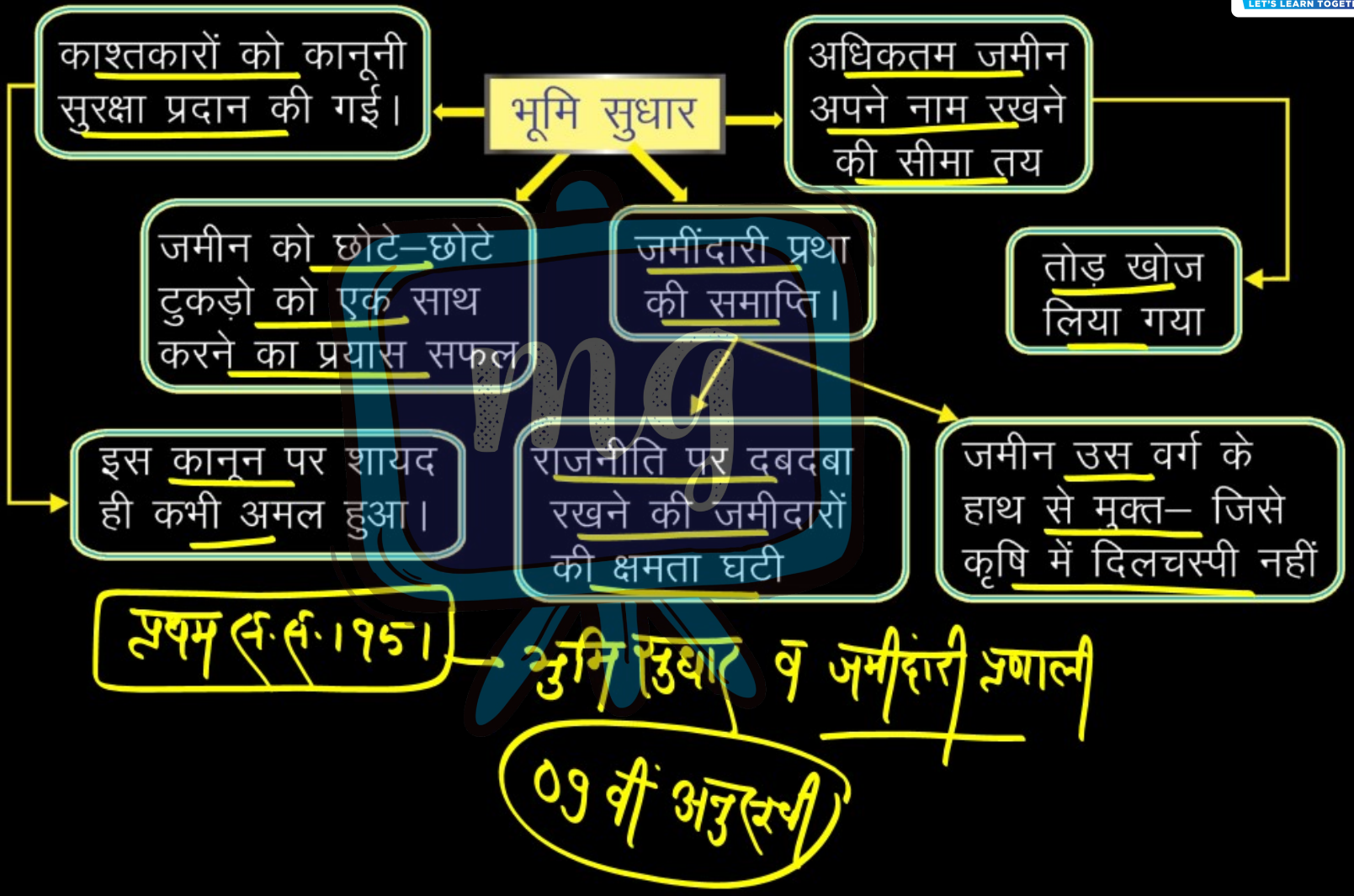
missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

बुनियाद :-

- नियोजित विकास के शुरूआती दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी।
- भाखड़ा - नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे - इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा-उत्पादन आदि इस अवधि में शुरू हुए।
- परिवहन और संचार के आधारभूत ढाँचे में भी काफी इजाफा हुआ।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by
ipca | Foundation

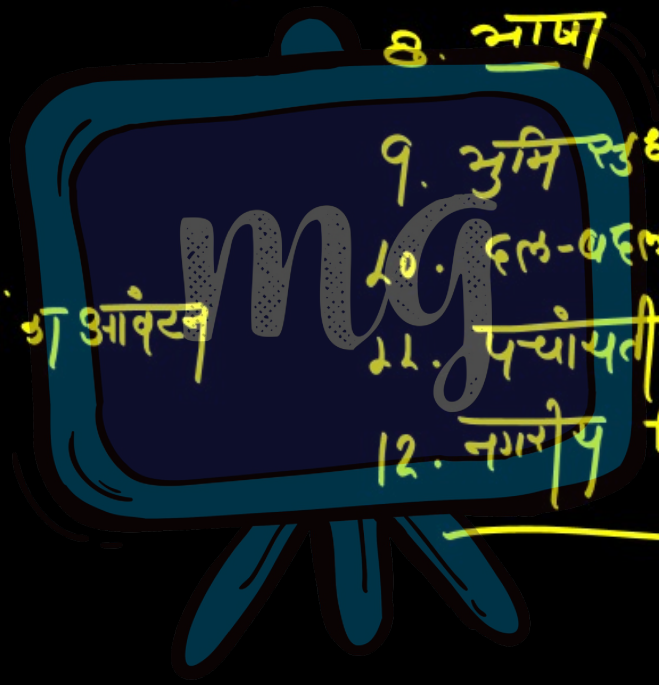
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

अनुसूची

08

12

1. संघ-राज्य
2. वेतन-भत्ते
3. शपथ
4. राज्यसभा सीटों का आवंटन
5. SC/ST
6. ST
7. सूची
8. भाषा
9. भूमि सुधार
10. दल-बदल
11. पंचायतीराज
12. नगरीय निकाय



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

सच्चाई :-

- कृषि के बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों को अमल में लाना अत्यन्त कठिन।
- भू-स्वामी बहुत ताकतवर थे।
- इनका राजनीतिक रसूख भी था।
- इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप ना ले सकें या कानून बनकर महज कागज की शोभा बढ़ाते।